

सीबीजी प्लांट्स की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर

आने वाले समय में थोड़ा सा भी गोबर

यमुना में न जा पाए : अमित शाह

हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी देशवासी चाहते हैं कि यमुना नदी का जल स्वच्छ हो, लेकिन यह कल्पना यमुना नदी में गिरने वाली गंदगी के निकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यमुना जी के शुद्धिकरण के संकल्प की सिद्धि की दिशा में यह समझौता एक अहम कदम है और आने वाले समय में थोड़ा सा भी गोबर यमुना जी में न जा पाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

बता दें कि केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने दिल्ली में गोबर के समुचित उपयोग के लिए कंफ्रेंसड बायो-गैस (सीबीजी) प्लांट्स की



स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन

सिंह, दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, केन्द्रीय गृह सचिव

और केन्द्रीय सहकारिता सचिव सहित केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लगभग 80 ट्रीटमेंट प्लांट्स पर शुरू हो चुका कार्य

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गटर के पानी और औद्योगिक कचरे के शुद्धिकरण के लिए दिल्ली में लगभग 80 ट्रीटमेंट प्लांट्स पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में थोड़ा सा भी गोबर यमुना जी में न जा पाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सवा लाख मवेशियों के अपशिष्ट के निस्तारण के बिना यह संभव नहीं होगा। शाह ने कहा कि दिसंबर, 2028 तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक भी लीटर गंदा पानी यमुना नदी में न जाए।

प्रति किलो एक रूपया पशुपालकों को देने का प्रावधान

केन्द्रीय अमित शाह ने कहा कि नंगली, घोड़ा-गोयला और गाजीपुर अपशिष्ट निस्तारण प्लांट्स से गोबर की प्रोसेसिंग का काम पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता और देशभर के करोड़ों पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में यह प्रतीकालक पहल बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आज हुआ यह समझौता देशभर के सभी महानगरों के लिए और बाद में गोबर प्रोसेसिंग के माध्यम से देशभर के ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में प्रति किलो एक रूपया पशुपालकों को देने का प्रावधान किया गया है।

इस पहल से पशु पालकों की बढ़ेगी आय

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समझौता देश के सभी बड़े शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए एक मॉडल का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न सिर्फ पशु पालकों की आय बढ़ेगी, स्वच्छता भी बढ़ेगी, कंफ्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) प्राप्त होगी और ऑर्गेनिक खेती की दिशा में भी इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी।

मंजीत महल गैंग का

कुरव्यात बदमाश अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंजीत महल गैंग के कुरव्यात बदमाश लोकेश उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया है। इसके पास से छह कार्टून्स के साथ एक रिवॉल्वर बरामद की गई। राजस्थान पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार का इनाम घोषित किया था। आरोपी पहले हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और डकैती जैसे 20 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है।

डीसीपी नारा चैतन्य के अनुसार हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और लूटपाट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल खतरनाक अपराधियों, शार्पशूटर्स और गैंगस्टर्स को पकड़ने का काम साउथ वेस्टर्न रेंज को सौंपा गया है। 12 जुलाई को इंस्पेक्टर मनेन्द्र सिंह की टीम को सूर्या के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद टीम ने इसे गुरुग्राम के सेक्टर-29 मार्केट से पकड़ा। आरोपी लोकेश गोपाल नगर, नजफगढ़ का रहने वाला था और उसकी उम्र 33 साल थी।



■ हत्या, डकैती और रंगदारी केस में था वांटेड

उसका जन्म 1993 में हरियाणा के चरखी दादरी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसने दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वह 2014 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसके खिलाफ करीब 21 केस दर्ज होने का पता चल चुका है।

समयपुर बादली पुलिस पर दुर्व्यवहार के आरोप

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में समयपुर बादली थाने के स्टफफ पर जबरन घर में घुसने, गाली गलौच, धमकी देने और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। बुधवार को पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अफसरों का कहना है कि यह मामला 10 जुन को हुई एक महिला और उसके बेटे से यारपीट की घटना के संबंध है। इस मामले में सचिव, जीतू, भर्त और चिंता देवी को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने उनकी अंतिम जमानत की अर्जियां खारिज कर दी थीं। केस में जीतू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को अभी पकड़ा जाना है। आरोप लगाने वाली महिला आरोपी सचिव की बहन है। आरोपियों के घर पर होने की जानकारी मिलने पर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गई थी। हालांकि वे वहां नहीं मिले और घर पर धारा 35(3) बीएसएसएस के तहत एक नोटिस धरपा किया गया। मौजूदा तथ्यों के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी घर के अंदर नहीं गया। जबकि दूसरी घुसने, गाली-गलौच, धमकी देने या दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि पुलिस के पास मौजूद जानकारी से नहीं होती है। पुलिस की यह कार्रवाई ऊपर बताए गए मामलों की जांच के सिलसिले में और कानून के अनुसार की गई थी। गौरतलब है कि 10 जुन को जेजे कैप बादली की रहने वाली सूरज कला देवी पत्नी रघुनाथ दुबे ने अपने बेटे नरेंद्र दुबे पर मछली विक्रेताओं पिता पुत्रों पर मारपीट का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि वह बेटे के साथ मछली खरीदने गई थी। वापसी में उनका सचिव नामक मछली विक्रेता से झगड़ा हो गया था। बाद में सचिव का भाई जीतू और पिता भारत व मां चिंता देवी भी झगड़े में शामिल हो गये थे। पिता पुत्रों ने नरेंद्र पर लोहे के सिरिया, शराब की बोतल और पत्थरों से हमला किया था। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

तिलक नगर में 17 वर्षीय लड़के

ने गोली मारकर की खुदकुशी

हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

पश्चिम दिल्ली के तिलक नगर में 17 वर्षीय एक लड़के ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में युवक ने पिता की लाइसेंस राइफल का इस्तेमाल किया। शव का पोस्टमॉर्टम दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक हाथ से लिखा नोट मिला है, जिसमें मृतक ने सामाजिक अपराध बोध का जिक्र किया है।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को हुई। तिलक नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी इलाके में युवक अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। पुलिस ने कहा कि टीम के पहुंचने से पहले किशोर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि लड़के ने हाल में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और वह अपने

माता-पिता, एक भाई और दो बहनों के साथ रह रहा था। वह भाई-बहनों में सबसे छोटा था। शाम करीब पांच बजे घटना के समय लड़के के पिता और एक रिश्तेदार घर में मौजूद थे। युवक बाथरूम में गया और 12 बोर की राइफल से खुद को गोली मार ली। पुलिस के अनुसार हथियार का लाइसेंस मूलरूप से लड़के के दादा के नाम पर था, जो सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। बाद में लाइसेंस लड़के के पिता को हस्तांतरित कर दिया गया। पिता भी पहले सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। पुलिस ने कहा कि हथियार का लाइसेंस 2030 तक वैध है। लड़के के पिता लगभग दो दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं। वह छोले-कुलचे का ठेला लगाकर आजीविका कमाते हैं। घटनास्थल को फॉरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किये गये हैं। घटना के सिलसिले में किसी भी तरह की साजिश का अंदेशा नहीं है।

द्वारका में हथौड़े से वार कर हत्या में शामिल दो गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

द्वारका इलाके में एक मकान की बिक्री को लेकर हुए विवाद में 38 वर्षीय व्यक्ति की हथौड़े से वार कर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम नजफगढ़ निवासी अनिल ठाकुर (66) और बिहार निवासी राजू कुमार (28) बताये गये हैं।

पुलिस के मुताबिक नजफगढ़ निवासी अखिलेश मंडल (38) का शव 12 जुलाई को द्वारका सेक्टर 18 ए में मिला था। मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और टैटू बने



थे। मौके से मृतक की पहचान हो सकती ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला था। द्वारका के सिर पर चोट के निशान थे और टैटू बने

बाद जांच शुरू की गई। इस दौरान टीम ने मृतक की पहचान करने और आरोपियों का पता लगाने के लिए घटनास्थल और

आसपास के इलाकों में लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया। साथ ही तकनीकी निगरानी भी की। बाद में पता चला कि मृतक अनिल ठाकुर की सहमति से उसके आवास पर रह रहा था। हालांकि, अखिलेश की शराब की लत के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।

पुलिस ने बताया कि ठाकुर द्वारा अपना घर बेचने का फैसला करने के बाद विवाद बढ़ गया क्योंकि अखिलेश मंडल इसका विरोध कर रहा था। ठाकुर ने अखिलेश को 10 जुलाई को द्वारका के

सेक्टर 13 में बुलाया, जिसके बाद वह और राजू कुमार उसे करगिल चौक के पास ले गए और हथौड़े से उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों आरोपी नजफगढ़ के धरमपुरा भाग गए। जांचकर्ताओं के मुताबिक ठाकुर, मंडल के परिवार को जानता था और उसने हत्या के बाद जानबूझकर उन्हें गुमराह किया और उसकी गुमशुदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने से परिवार को रोका। पुलिस ने कहा कि उसने हत्या में इस्तेमाल खून से सने हथौड़े और पीड़ित का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है।

सभी पुलिस स्टेशनों और एएटीएस की कार्रवाई

द्वारका पुलिस के ऑपरेशन चक्र में

फंसे 30 वाहन चोर, 64 केस सुलझे

हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के तहत 30 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही 64 केस सुलझाने का दावा किया गया है। यह अपनी तरह का पहला जिला व्यापी रिकवरी अभियान रहा।

डीसीपी कुशल पाल सिंह के अनुसार ऑपरेशन चक्र वाहन चोरी और उससे जुड़े सड़क अपराधों पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य आदतन वाहन चोरों, चोरी के वाहन खरीदने वालों और बार-बार



अपराध करने वालों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना था। ऑपरेशन के दौरान सभी पुलिस

स्टेशनों और एएटीएस टीम ने जिले भर में इंटीलेजेंस आधारित छापेमारी, निगरानी, एनएपीआर

मॉनिटरिंग और सघन पिकेट चेंकिंग करके बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और समर्पण दिखाया। 30 वाहन चोर पकड़े गए। 64 चोरी के वाहन बरामद किए गए।

इनमें 61 दुपहिया और तीन चार पहिया वाहन शामिल हैं। पकड़े गये लोगों में 17 बार-बार अपराध करने वाले शामिल हैं। चार कुख्यात अपराधी (बीसी) पकड़े गए। चिह्नित पार्किंग स्थानों से 36 वाहन बरामद हुये। आदतन अपराधियों से 23 वाहन बरामद किये गये। पिकेट चेंकिंग के दौरान तीन वाहन पकड़े। एएनपीआर आधारित दो वाहन बरामद हुये।

यमुना में डूबे चार में से

एक किशोर का मिला शव



हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

अलीपुर थाना क्षेत्र के हिरणकी गांव में तीन दिन पहले यमुना में नहाते वक्त तेज धारा में बह गए चार में से एक नाबालिग लड़के का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। तीन अन्य की तलाश में बोट क्लब की टीम जुटी है। पुलिस के अनुसार दिल्ली बोट क्लब की सहायता से उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में यमुना नदी से राहुल नामक लड़के

का शव बरामद किया गया। 15 साल का राहुल पिता सतीश और परिवार के अन्य सदस्य के साथ इब्राहिमपुर गांव में रहता था। कादीपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला राहुल दसवीं कक्षा का छात्र और एनसीसी कैडेट था। पुलिस का कहना है कि जब तक सभी छात्रों का पता नहीं चल जाता, तब तक अभियान जारी रहेगा।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और दिल्ली पुलिस की टीमों तीन अन्य लड़कों अंशू, सौरभ और अमनदीप की तलाश कर रही हैं। पुलिस को संदेह है कि लगभग 15 साल के लड़के नदी की तेज धारा में काफी दूर तक बह गए हैं। चारों लड़के 12 जुलाई को नदी में नहाने गए थे।

पुलिस ने यौन शोषण केस में

11 दिन में दाखिल की चार्जशीट

हरिभूमि न्यूज़ ॥ नई दिल्ली

शदी का झूठा वादा करके यौन शोषण के मामले में जनकपुरी पुलिस स्टेशन ने 11 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि केस में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केस के सिलसिले में सीडीआर और लोकेशन एनालिसिस सहित वैज्ञानिक और तकनीकी जांच की गई।

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ जनकपुरी पुलिस स्टेशन ने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पेशेवर, वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच की गई। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी, आसिफ उर्फ हनी ने अपना धर्म छिपाया, शदी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शदी करने से इनकार कर दिया। उसके साथ मारपीट की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। यहाँ नहीं उसकी निजी

तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी गई थी। जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया गया। शिकायतकर्ता का विस्तृत बयान दर्ज किया गया। आरोपी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई और कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया। फॉरेंसिक जांच के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसका मोबाइल फोन जब्त किया गया। मेडिकल जांच के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साइट प्लान तैयार किया और सभी संबंधित मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत एकत्र किए। तकनीकी जांच में आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा का विश्लेषण शामिल है। उनके बीच लगातार बातचीत की पुष्टि हुई। आरोपी के कार्यस्थल से उसकी उपस्थिति के रिकॉर्ड भी इकट्ठा किए गए और उन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया। तेज, पेशेवर और वैज्ञानिक जांच के कारण पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए जा सके, जिससे जांच अधिकारी ने तेजी से जांच पूरी की और एफआईआर दर्ज होने के 11 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई।

उत्तर रेलवे			
खुली निविदा सूचना			
भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य संकेत एवं दूर-0 संचार अभि०/प्रोजेक्ट यूनिट दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई-टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।			
N.I.T. No.		Project_DLI-SNT_26_10 dated 14.07.2026	
कार्य का नाम	उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अंतर्गत पानीपत-रोहतक और रोहतक-अस्थल बोहर-रेवाड़ी (HUN) सेक्शन में TVU>10000 वाले लेवल क्रॉसिंग (LC) गेटों के इंटरलॉकिंग के लिए (सिग्नल एवं टेलीग्राफ) कार्यों के लिए टेंडर।		
अनुमानित लागत	₹2,43,64,623.45	बिगोहर राशि	₹4,87,300/-
समाप्ति अवधि	12 महीने		
ई-निविदा खोलने और प्रस्तुत करने के लिए दिनांक और समय	05.08.2026 को 11:30 बजे तक तथा प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने का समय दिनांक 05.08.2026 को 11:30 बजे		
निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है।	www.irops.gov.in पर उपलब्ध है।		
पत्र संख्या: Project_DLI_SNT_26_10		दिनांक: 14.07.2026	2429/2026
आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ			

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा	
धारा 82 Cr. P.C./84BNSS देखिए	
मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, मोहसिन उर्फ मोसिन कुरेशी, पुत्र: यामीन कुरेशी, पता: 9/4338-D/G-F, खसरा नंबर 156 से 158 और 161, गली नं. 8, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली, ने FIR No. 619/2025, U/s: 318(4)/3(5), धाना: बदरपुर, नई दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, मोहसिन उर्फ मोसिन कुरेशी, मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, मोहसिन उर्फ मोसिन कुरेशी, फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 619/2025, U/s: 318(4)/3(5), धाना: बदरपुर, नई दिल्ली, के उक्त अभियुक्त, मोहसिन उर्फ मोसिन कुरेशी, से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 20.08.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।	
आदेशानुसार श्री विनोद जोशी,	
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दक्षिण पूर्व जिला, कमरा नं. 515 साकेत कोर्ट, नई दिल्ली	
DP/9593/SE/2026 (Court Matter)	

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा	
धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 देखिए	
मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राधे श्याम पुत्र अमरनाथ, निवासी 59, ए-ब्लॉक, फेज-4, मेट्रो विहार, होलंसी कलां, दिल्ली-82, ने CC NI Act No. 1164/2021, U/S 138 NI Act, पुलिस स्टेशन के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी जिला, नई दिल्ली-85, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राधे श्याम मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त राधे श्याम फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि CC NI Act No. 1164/2021, U/S 138 NI Act, पुलिस स्टेशन के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी जिला, नई दिल्ली-85, के उक्त अभियुक्त राधे श्याम से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 28.09.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।	
आदेशानुसार श्री आकाश शर्मा	
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-03, (उत्तर), कोर्ट नं०-213, द्वितीय तल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली	
DP/9693/RD/2026 (Court Matter)	

उत्तर रेलवे	
निविदा सूचना	
उप मुख्य अभियंता/निर्माण-1, उत्तर रेलवे, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए एक पैकेट सिस्टम के अधीन खुली ई. टेंडर आमंत्रित की जाती है।	
1. कार्य	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, कस्मरी गेट, दिल्ली के कार्यालय परिसर, का ऑडिट कार्यालय और उप मुख्य अभियंता/निर्माण-1, कार्यालय और अधिकारी विश्राम गृह, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली में अच्छी प्रकार से विकसित सजावटी पौधों नाम सहित गमलों की आपूर्ति एवं रख रखाव 24 (बीबीसी) माह के लिए।
2. कार्य की अनुमानित लागत	₹ 182-34 लाख (रुपये एक करोड़ बीस लाख बीतीस हजार मात्र)
3. पूर्ण करने की अवधि	24 (बीबीसी) माह
4. बिड सिक्कोरिटी (केश/बी.जी.) राशि	₹ 3,64,700/- (रुपये तीन लाख सैसठ हजार सात सौ मात्र)
5. रेलवे वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र की बिक्री/उपलब्धता	निविदा दस्तावेज IREPS की वेबसाइट www.irops.gov.in पर दिनांक 14.07.2026 से 05.08.2026 को 15.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
6. टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख व समय	दिनांक 05.08.2026 को 15.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। निविदा दस्तावेज IREPS की वेब साइट www.irops.gov.in पर दिनांक 22.07.2026 से 05.08.2026 को 15.00 बजे तक निविदाकार द्वारा अपलोड की जा सकती है।
7. निविदा खोलने की तारीख व समय	दिनांक 05.08.2026 को 15.00 बजे खोली जाएगी।
सं. 220-Acs-1-1301-Horti-KG दिनांक : 14.07.2026	2428/2026
आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ	

आप नहीं बचा पाई अपनी वर्तमान चार वार्ड समिति, दो से ही करना पड़ा संतोष

वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा बनी 10 नंबरी, क्रॉस वोटिंग ने डुबोई आप की लुटिया

सत्यप्रकाश ►► नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड समितियों पर बुधवार को हुए चुनाव में भाजपा ने 10 पर कब्जा करते हुए सत्ता की ताकत बढ़ाई है। जबकि कांग्रेस ने न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली कहावत को सही साबित करते हुए कहीं भाजपा का साथ दिया तो कहीं आप पार्टी के संग दिखी। वहीं आम आदमी पार्टी की लुटिया उसके ही पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके डुबो दी, जिससे उसे केवल 2 वार्ड समिति पर ही जीत नसीब हुई।

इसमें भी रोहिणी वार्ड समिति पर अंदर खाते कांग्रेस का वोट मिलने से आप पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं करोल बाग जोन में भाजपा ने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था, इसलिए यहां निर्विरोध जीत तय हुई। इसी प्रकार स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने पांच पर शानदार जीत हासिल की जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में केवल करोल बाग से स्थायी समिति सदस्य के लिए राजन अरोड़ा ने जीत दर्ज की है। संख्या बल के हिसाब से कुल 12 वार्ड समितियों में से आठ वार्ड समितियों में भाजपा के पास बहुमत था। जबकि चार में आप



पार्टी के पास, बावजूद इसके आप और भाजपा ने 11-11 वार्ड समितियों में प्रत्याशी उतारे थे। शाहदरा जोन में भाजपा के यशपाल सिंह को चेयरमैन के लिए 18 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। जबकि आप प्रत्याशी को उम्मीदवार को 6 वोट के साथ हार का मुंह देखना पड़ा।

वहीं डिप्टी चेयरमैन पद के लिए भाजपा के ही राजू सचदेव निर्विरोध चुने गए। सिविल लाइन वार्ड समिति के अध्यक्ष पद के लिए लगातार दूसरी बार भाजपा के गुलाब सिंह राठौर ने जीत हासिल की। वहीं भाजपा के मनोनिर्त सदस्य संजय त्यागी ने डिप्टी चेयरमैन के रूप में जीत दर्ज की है। यहां आप को हार का मुंह देखना पड़ा। शाहदरा साउथ में अध्यक्ष यशपाल सिंह ने 24 में

से 18 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। शाहदरा नॉर्थ में पंकज लुथरा और बृजेश सिंह को 20-20 वोट मिले। साउथ जोन में धर्मवीर सिंह और ममता यादव ने 12-10 के अंतर से जीत हासिल की। नरेला में जनता देवी 13 वोट के साथ चेयरमैन चुनी गई, जबकि दिनेश कुमार डिप्टी चेयरमैन चुने गए। वहीं शाहदरा जोन में भाजपा के सुनेश स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर चुने गए। वहीं करोल बाग, केशव पुरम, नरेला, सेंट्रल, नजफगढ़ और शाहदरा साउथ जोन सहित कुल स्थायी समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए। जिसमें से केवल एक करोल बाग में आप पार्टी के पार्षद का जीत मिली, जबकि पांच जोन में भाजपा के पार्षदों ने स्थायी समिति सदस्य के लिए जीत दर्ज

एआईएफबी व वक्त टांक की बगावत से भाजपा बनी सिंकदर

सिटी सदर पहाड़गंज जोन में अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा को एआईएफबी और आप के पार्षदों ने वोट कर जितया है। भाजपा की उषा शर्मा को 7 वोट मिले जबकि बहुमत वाली आप को 5 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। यहां पर भाजपा के पास 7 पार्षदों का आंकड़ा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मौजूदा वार्ड अध्यक्ष रहे विकास टांक ने बगावत कर भाजपा का दामन थाम लिया जिससे वार्ड के समीकरण में बदलाव आ गया। वहीं एआईबीएफ के पार्षद ने भाजपा को वोट दिया और जबकि एक आप पार्षद ने भी भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोट कर अध्यक्ष पर भी जीत दिलाई। यहां पर राजनीतिक दलों का समीकरण देखे तो चुनाव से ठीक पहले तक आप के पास 7 पार्षदों का आंकड़ा था, विकास टांक के जाने के बाद आप के 6 पार्षद बचे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के 4 पार्षद, आईबीपी के 1 पार्षद और एआईएफबी के 1 पार्षद हैं। यहां पर भाजपा की उर्षा शर्मा को 7 वोट मिले हैं, जिससे आप पार्षदों का भी एक वोट शामिल है।

की। इस प्रकार स्थायी समिति में भी भाजपा का भरपूर दबदबा बना रहेगा।

वेस्ट जोन में भाजपा ने किया चेयरमैन पद पर कब्जा, लगा क्रॉस वोटिंग का दंश

वेस्ट जोन पर भी आप पार्टी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और यहां भाजपा ने जीत दर्ज की। इस जोन में कुल 25 वोट पड़े, जिसमें से भाजपा के हरीश ओबरोय को 14 वोट पड़े और आप पार्टी प्रत्याशी को केवल 11 वोट मिले। जबकि आप को केवल डिप्टी चेयरमैन पद पर डिम्पल आहुजा की जीत से ही संतोष करना पड़ा। यहां भी आप पार्टी अपने पार्षदों पर नियंत्रण रखने में विफल रही और उसके 2 पार्षदों ने धोखा देते हुए क्रॉस वोटिंग कर भाजपा की जीत तय कर दी।



रोहिणी जोन में भाजपा की बनती बात बिगड़ी, कांग्रेस ने दिया आप का साथ!

रोहिणी जोन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां आप की पुष्पा सोलंकी की जीत हुई। उन्हें कुल 12 वोट मिले हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी को 11 वोट मिले। वहीं डिप्टी चेयरमैन के पद पर आप के रमेश चंद चुने गए। उन्हें 12 वोट मिले। रोहिणी जोन में आप के 11 पार्षद हैं, जबकि भाजपा के पास 8 पार्षदों का आंकड़ा था, लेकिन आईबीपी के 2 पार्षद के भाजपा में शामिल होने से यह आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया। ऐसे में यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या रोहिणी जोन में कांग्रेस के 2 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग ने भाजपा की बनती बात बिगड़ दी। यह फिलहाल अंदर खाते की बात है।



नजफगढ़ जोन में आप पार्षदों ने नाम लिया वापस

आप पार्टी को नजफगढ़ वार्ड समिति में भी बड़ा झटका लगा और उसके तीनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। तीनों का तर्क है कि हमें विकास कार्य करवाने हैं चाहे कोई भी करे इसलिए भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। यहां भाजपा चेयरमैन पद पर जयवीर सिंह राणा, डिप्टी चेयरमैन पद पर सुष्मा राठी और स्थायी समिति सदस्य पद पर शशि यादव की जीत हुई। वहीं दक्षिण जोन में चेयरमैन पद पर धर्मवीर सिंह ने 12 वोट के साथ जीत दर्ज की। जबकि जबकि डिप्टी चेयरमैन पद ममता यादव को भी 12 वोट मिले। वहीं आप के दोनों उम्मीदवारों को 10-10 वोट के साथ हार का मुंह देखना पड़ा।



आप पार्टी ने निगम वार्ड समिति चुनाव में कांग्रेस पर लगाए भाजपा का साथ देने के आरोप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की वार्ड समितियों के हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि उसने भाजपा का साथ दिया है। इस मुद्दे पर आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में साउथ जोन में आप के 10, भाजपा के 10 और कांग्रेस के 2 पार्षद थे, लेकिन भाजपा को 12 वोट मिले। इससे साबित होता है कि कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया और उसके पक्ष में वोट डाले। वहीं दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा महापौर के गृहक्षेत्र रोहिणी जोन से आप पार्टी ने भाजपा को हराकर शानदार जीत दर्ज की है।

आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विकास टांक भाजपा में हुए शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और वांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेरावाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और वाल्मीकि समाज के युवा नेता विकास टांक बुधवार को मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा संयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा में शामिल हुए। कपूर ने कहा कि पुरानी दिल्ली से 3 बार के पार्षद विकास टांक वाल्मीकि समाज में और क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी का पटका पहनाकर, मिस्ट्र कॉल से सद्स्यता करवा कर और मिठाई खिलाकर विकास टांक का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज यह बतते हुए खुशी हो रही है कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली नगर निगम सिटी एस पी. जोन के चेयरमैन विकास टांक भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

एसआईआर के लिए अब सत्यापन आठ अगस्त 2026 तक बढ़ा : सीईओ

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने दिल्ली में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। सीईओ के इस फैसले के बाद अब अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार, बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन 8 अगस्त 2026 तक किया जाएगा जबकि पहले यह 29 जुलाई 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम था। इसके बाद 17 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। मतदाता 17 अगस्त से 16 सितंबर तक अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित कराने के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। आयोग ने सभी संबधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप से नई समय-सारिणी की जानकारी देने को कहा गया है। सीईओ ने बताया कि इस संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मतधिकार का प्रयोग कर सके।

दिल्ली में तय समय-सीमा में सरकारी सेवाएं देना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली में अब तय समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब नागरिकों को समयबद्ध व सुगम सरकारी सेवाओं का कानूनी अधिकार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि इस कानून से सेवा-व्यवस्था में प्रभावी सुधार होगा साथ ही यह नया कानून जवाबदेही तय करेगा और देरी पाई गई तो अधिकारियों का पक्ष जानने के बाद निर्धारित जुर्माना भी लगेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा



है कि इस कानून के लागू होने से नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं मिलेंगी, अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर कम होंगे, डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी, अधिकारियों की

जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे शासन व्यवस्था अधिक दक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील, नागरिक-केंद्रित और विश्वसनीय बनेगी तथा

- दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी
- नागरिकों को मिलेगा समयबद्ध व सुगम सरकारी सेवाओं का कानूनी अधिकार

सरकारी सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने नागरिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू ट्राइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल, 2026 (दिल्ली) -नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक, 2026) को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

दिल्ली में दस में से एक सरकारी स्कूल की इमारत खतरनाक: यादव

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में दस में से एक सरकारी स्कूल की इमारत असुरक्षित और खतरनाक हालत में पहुंच चुकी है। स्कूलों की ऐसी हालत के लिए वर्तमान में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार और शिक्षा मॉडल की दुहाई देने वाली 11 वर्षों तक सत्तासीन रही केजरीवाल सरकार है। दिल्ली सरकार के अधीन कुल 1270 स्कूलों में 799 सरकारी और 471 सरकारी मदद वाले स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों की 108 स्कूल इमारतों की जांच सामने आने पर 54 स्कूल इमारतों को गिराने के आदेश दिए गए हैं। जिससे साफ हो गया है कि जहां आम आदमी पार्टी ने स्कूल इमारतें बनाने के नाम पर केवल कमरों की लिफाई पोशाक की उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की इमारतों की भी यही हालत है। यादव ने कहा कि बीबीपी की दिल्ली सरकार ने जल्द स्कूल इमारतों और दो शिफ्टों में चल रहे 284 स्कूलों को एक शिफ्ट में तब्दील करने के लिए प्रति वर्ष 10 स्कूल बनाने का वादा किया था।

शालीमार बाग में 'हीट स्मार्ट स्कूल' पायलट का उच्च-स्तरीय निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली में गर्मी और हीटवेव के प्रभावों से बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बुधवार को शालीमार बाग स्थित बी. टी. ब्लॉक के सर्वोच्च बाल विद्यालय में 'हीट स्मार्ट स्कूल' पायलट का उच्च-स्तरीय निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का आयोजन जिला प्रशासन, मध्य-उत्तर जिला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और जीआईजेड इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान विद्यालय में विकसित किए गए ऐसे व्यावहारिक और विस्तार योग्य उपयों का अवलोकन किया गया, जिनका उद्देश्य अत्यधिक गर्मी के दौरान विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'हीट स्मार्ट स्कूल' पायलट से जुड़े सभी विभागों और साझेदार संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बदलते जलवायु परिदृश्य में ऐसे नवाचारी प्रयास समय की आवश्यकता हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मॉडल राजधानी के अधिक विद्यालयों तक पहुंचेगा और सुरक्षित एवं जलवायु-अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वांगचुक की तबीतय हुई और खराब थरूर ने लिखा पत्र, सांसद चंद्रशेखर सहित कई नेता पहुंचे मिलने



हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

कांग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) का धरना बुधवार को लगातार 26वें दिन भी जारी रहा। वहीं लगातार भूख हड़ताल पर चल रहे सोनम वांगचुक की अनशन के 18वें दिन तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टरों के अनुसार अब तक वांगचुक का वजन 8.5 किलो तक गिर चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम वांगचुक का वजन अब 57.15 किलोग्राम रह गया है। मंगलवार को जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च में अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो। जिससे की केंद्र सरकार की आंखें खुले और वह सोचने पर मजबूर हो। संगठन ने कहा कि अब सवाल

चीफ व सांसद चंद्रशेखर तथा सांसद प्रताप पडोले सहित कई अन्य लोग वांगचुक से मिलने पहुंचे। वांगचुक की तबीयत को लेकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संसद को कोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह ज़िद अच्छी नहीं है, 18 दिन से वांगचुक भूखे हैं, केवल छात्रों के लिए। बावजूद इसके केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने या बात करने तक नहीं आया। उन्होंने आह्वान किया कि आने वाली 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च में अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो। जिससे की केंद्र सरकार की आंखें खुले और वह सोचने पर मजबूर हो। संगठन ने कहा कि अब सवाल

यह नहीं है कि विपक्ष का कौन-सा नेता आंदोलन के समर्थन में आया या नहीं। बल्कि असली सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री को अब तक जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया।

डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में पानी की मात्रा फिलहाल ठीक है और वह मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं। वहीं बुधवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पत्र लिखकर वांगचुक से अनशन तोड़ने के अपील की। भीम आर्मी

प्रति दिन 250 रुपये का दंड, अधिकतम सीमा 5,000 रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेष बात यह है कि इस विधेयक में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है। बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपये का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी, लगाया जा सकेगा। हालांकि अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर दिया जाएगा, जिससे प्राकृतिक व्ययय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा।

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त हो। साथ ही, सरकारी विभागों और अधिकारियों को सेवा प्रदान करने में होने वाली देरी तथा लापरवाही के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाए। यह कानून दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल, प्रभावी और तकनीकी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर बनेगा।

‘समयबद्ध सेवा का नया कानून बदहाल इंटरनेट व्यवस्था में नहीं कारगर’

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक, 2026)' को मंजूरी देकर दावा किया है कि अब नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे सुशासन और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। हालांकि, जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई व्यावहारिक सवाल भी सामने आ रहे हैं।

ओबीसी समेत अनेक प्रमाणपत्रों का निगमन इंटरनेट आधारित पोर्टलों के माध्यम से होता है। ऐसे में यदि नेटवर्क या डिजिटल अवसंरचना बाधित होती है तो तय समय-सीमा में सेवाएं देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करीब दो माह पहले दिल्ली के 'आउटर नॉर्थ राजस्व जिले' में एक ही महीने के भीतर दो बार 'एमटीएनएल की ऑफ्टिकल फाइबर केबल क्षतिग्रस्त' होने की घटनाएं सामने आई थीं। अधिकारियों के अनुसार, सड़क कटिंग और विभिन्न एजेंसियों द्वारा 'खुदाई' के दौरान केबल को नुकसान पहुंचा, जिससे इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुईं। इसका असर राजस्व कार्यालयों, दिल्ली नगर निगम और अन्य कई सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं पर भी पड़ा और कई नागरिकों को प्रमाणपत्र जारी होने में देरी का सामना करना पड़ा।

संवेदनशील डेटा का हो सकता है दुरुपयोग सूत्रों के अनुसार, सरकारी इंटरनेट सेवाएं बंद होने की ऐसी परिस्थितियों में कुछ कार्यालयों द्वारा निजी, वैकल्पिक इंटरनेट कनेक्टिविटी का सहारा लिया जाता है। हालांकि, इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि सभी मामलों में निजी इंटरनेट सेवाओं का उपयोग किया जाता है या नहीं। यदि किसी सरकारी कार्यालय में बहुत जरूरी कार्य के चलते निजी कंपनियों का इंटरनेट का उपयोग होता है तो ऐसी स्थिति में 'संवेदनशील नागरिक डेटा लीक' भी हो सकता है।

दंड से पहले व्यवस्थागत कमियों को दूर करना भी जरूरी

इस नए कानून के मामले में नाम नहीं छापने की शर्त पर राजस्व और एमसीटी के कुछ अधिकारियों का कहना है कि केवल समय-सीमा तय कर देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि इंटरनेट सेवाएं बार-बार बाधित होती हैं, सर्वर डाउन रहते हैं, विभागों के बीच समन्वय की कमी रहती है या तकनीकी अवसंरचना कमजोर रहती है, तो अधिकारियों पर दंड लगाने से पहले इन व्यवस्थागत कमियों को भी दूर करना होगा।

महिला यात्रियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस शुरू करेगी सरकार

महिला को सुरक्षित यात्रा करने का है अधिकार: पंकज

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

हर महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा करने का अधिकार है। कामकाजी महिलाओं के लिए समर्पित यह बस नेटवर्क दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक सुरक्षित, सुलभ और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करेगी। डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने राजधानी में महिला यात्रियों



के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के मकसद से सिर्फ महिलाओं के लिए

समर्पित इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार की यह प्रस्तावित पहल राजधानी दिल्ली में अधिक सुरक्षित, ज्यादा समावेशी और महिला केंद्रित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री डॉ. पंकज के अनुसार, इस प्रस्तावित नेटवर्क के तहत महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 समर्पित इलेक्ट्रिक बस सर्विस शामिल हैं। इन्हें राजधानी दिल्ली के 15 प्रमुख व्यस्त रूट पर 30 लेडीज स्पेशल नाम से बस सेवाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ

कॉलेज छात्राओं के लिए 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवा

मंत्री ने बताया कि इसी तरह 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सर्विस को कॉलेज को शेड्यूल के हिसाब से प्लान किया गया है। ये बस सर्विस नजफगढ़, रोहिणी, जनकपुरी, मुंडका, मयूर विहार, कालकाजी, पटला और धौलाकुआं जैसे बड़े रिहायशी इलाकों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैम्पस समेत कई प्रमुख कॉलेजों से सीधे जोड़ेगी। इस विशेष पहल से सुबह-शाम के समय सफर करने वाली छात्राओं के लिए आने-जाने के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी।

कैम्पस समेत दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों और प्रमुख रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 13 समर्पित रूटों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवाएं शामिल हैं।

मंत्री से मिली जानकारी के अनुसार, 30 लेडीज स्पेशल बसों ऑफिस के व्यस्त समय (पीक आवर्स) के दौरान दोनों दिशाओं में चलेंगी। सुबह की सेवाएं प्रातः 7 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह के 9

बजे के बीच चलेंगी और वापसी की सेवाएं शाम को 4 बजकर 32 मिनट से लेकर 6 बजकर 15 मिनट के बीच संचालित होंगी। ये बसें राजधानी दिल्ली के प्रमुख रोजगार केंद्रों, कमर्शियल इलाकों, इंस्टीट्यूशनल हब और प्रमुख मेट्रो इंटरचेंज स्टेशनों को जोड़ेंगी, जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा संभव हो सकेगी।

खबर संक्षेप

लाल बहादुर यादव बने अध्यक्ष

फरीदाबाद। सेक्टर 56-56ए स्थित रैजिडेंट्स वेलफेयर कमेटी के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुए। चुनाव समिति द्वारा जारी घोषणा के अनुसार प्रत्येक पद के लिए केवल एक-एक वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में हेमचंद्र शर्मा को चेयरमैन तथा लाल बहादुर यादव को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है।

800 विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा में किया जागरूक

फरीदाबाद। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से फरीदाबाद पुलिस की रोड सेफ्टी सेल ने पिछले सप्ताह जिले के तीन प्रमुख विद्यालयों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस जयबीर सिंह के निदेशन में आयोजित इस अभियान में करीब 800 विद्यार्थियों, स्कूलों के ट्रांसपोर्ट स्टॉफ और वाहन चालकों ने भाग लिया। सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में व्यवहारिक जानकारी देकर जिम्मेदार रोड सेफ्टी स्कॉलर्स प्राइड स्कूल सेक्टर-16 तथा डीपीएस ग्रेटर में अलग-अलग जागरूकता सत्र आयोजित किये।

ठगी के मामले में खाता धारक गिरफ्तार

फरीदाबाद। फोन हैक कर 98500 रुपए की ठगी के एक मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने 14 जुलाई को संदीप गौर निवासी लखनउ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। जिसको न्यायलय में पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार एसजीएम नगर निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना एनआईटी में दी अपनी शिकायत में बताया कि 27 मई को उसके व्हाट्सएप पर एक अंजान नंबर से लिंक आया। जिस पर क्लिक करते ही उसका फोन हैक हो गया और उसके खाता से 98500 रुपए कट गए, जिसकी शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

मखाने की फर्म की आड़ में चला रहे थे फर्जी काल सेंटर नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवक व युवतियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 गिरफ्तार



हरिभूमि न्यूज़ ►► गाजियाबाद

स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च व थाना साहिबाबाद पुलिस ने, संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवक व युवतियों को ठगता था। मखाने की फर्म की आड़ में यह फर्जी काल सेंटर चलाया जा रहा था। दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय इस गिरोह के कुल 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिनमें कई

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण



उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और कॉरपोरेट क्षेत्र को इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए।

अधिकारियों के साथ इंदिरापुरम पहुंचे नगर आयुक्त

इंदिरापुरम में नए बने हुए नालों में से हटारे गए अवरुद्ध, चल रहे कार्य स्थलों पर कराई गई बैरिकेडिंग



जिसका लाभ क्षेत्र वासियों को मिलेगा, सुंदर सड़कों के साथ-साथ व्यवस्थित सुविधा का भी ध्यान रखा गया है जल भराव ना हो नालों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी निगम द्वारा की गई है। चल रहे निर्माण के कार्यों में बारिश से होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए इंदिरापुरम का दौरा समस्त विभागीय अधिकारियों व टीम के साथ किया गया,

मिट्टी हटाने का कार्य भी कराया जा रहा है आवश्यकता को देखते हुए अस्थाई रूप से अप्रोच रोड बनाई जा रही हैं, नगर आयुक्त द्वारा इंदिरापुरम निवासियों के लिए गांधियाबाद नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में बारिश के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े विशेष ध्यान रखने के लिए निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार चौधरी तथा अन्य विभाग को निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित अपर नगर आयुक्त अर्जुन कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गणितिलेश, महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद, प्रभारी उद्यान डॉक्टर अनुज, तथा अन्य समस्त विभागों की टीम को एक साथ योजना तथा समन्वय बनाते हुए इंदिरापुरम में चल रहे कार्यों से निवासियों को असुविधा न हो विशेष ध्यान रखने के लिए को निर्देशित किया गया।

हरिभूमि न्यूज़ ►► फरीदाबाद

छांयसा के पास कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे पर चलती कार की छत पर बैठकर सफर करना एक युवक को महंगा पड़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक का 14 हजार रुपए का पोस्ट चालान कर दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह अपनी और दूसरों की जान जोखिम में

डालने वाली हरकतें बिल्कुल न करें। जानकारी के अनुसार करीब चार दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक सेंट्रो कार केजिपी एक्सप्रेसवे पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कार में बड़ी मात्रा में सब्जियां भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि कार में जगह नहीं बची थी, इसलिए एक युवक कार की छत पर बैठकर सफर कर रहा था। उसी समय पीछे चल रहे एक अन्य वाहन

डाइवर ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच में वाहन की पहचान होने पर पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न नियमों के उल्लंघन के तहत वाहन मालिक का 14 हजार रुपए का पोस्ट चालान किया। चालान में यातायात नियमों की कई धाराओं के

पौधों की देखभाल का संकल्प लिया

सेक्टर 56-56 ए की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सीपीडब्ल्यूडी की जमीन पर चलेगा बुलडोजर, 26 जुलाई से होगी तोड़फोड़ शुरू

हरिभूमि न्यूज़ ►► फरीदाबाद

सेक्टर-22 स्थित शिव नगर और मुजेयर इलाके में सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) की जमीन पर मकानों को खाली करने के नोटिस के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि वह पिछले 30 से 40 सालों से यहां पर रह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ विभाग ने 26 जुलाई से तोड़फोड़ का काम शुरू करने का दावा किया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता सुरेश कुमार के मुताबिक मुजेयर, सारन और सेक्टर-22 में गर्वमेंट प्रैस की करीब 6 एकड़ जमीन है। करीब 25 साल पहले गर्वमेंट प्रैस बंद होने के बाद यह जमीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो गई थी। विभाग की ओर से इस जमीन का कोई उपयोग नहीं किया गया। जिसके बाद यहां पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जे कर लिए। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से पहले भी नोटिस दिया गया था। जिसको लेकर लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट की ओर से भी अब जमीन को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। एसडीएम त्रिलोकचंद ने बताया कि तोड़फोड़ से पहले नियम अनुसार मुजेयर, सारन और सेक्टर-22 में गर्वमेंट प्रैस की करीब 6 एकड़ जमीन है। करीब 25 साल पहले

घर में चोरी का तीसरा आरोपी धराया

आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा

हरिभूमि न्यूज़ ►► फरीदाबाद

क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 ने घर में लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने के मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी पहचान दीपक निवासी संजय कॉलोनी फरीदाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी के सामान में शामिल चार चांदी की पाजेब और एक चांदी की चेन बरामद की है। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल



भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार संजय एन्क्लेव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 मई 2026 को वह अपने परिवार के साथ खाटू श्याम राजस्थान दर्शन के लिए गया था। अगले दिन 30 मई की सुबह जब वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला।

सर्विस सेंटरों के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ऑनसाइटगो की क्यूडिजी संधालेगी क्रोमा के ओन लेबल उत्पादों की आफ्टर-सेल्स सेवा

हरिभूमि न्यूज़ ►► गुरुग्राम

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल क्षेत्र में आफ्टर-सेल्स सेवा को मजबूत करने की दिशा में क्रोमा ने अपनी सहायक कंपनी क्यूडिजी (ऑनसाइटगो समूह) को पूरे भारत में अपने ओन लेबल उत्पादों का अधिकृत सर्विस पार्टनर नियुक्त किया है। अब क्यूडिजी इंटरलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी सेवाओं का संचालन करेगी। कंपनी के अनुसार, पिछले छह महीनों में सेवा संचालन और तकनीकी प्रणालियों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन समेत अन्य घरेलू उपकरणों के लिए देशभर में 550 से अधिक सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, मरम्मत प्रक्रिया और सेवा अनुरोधों की रियल-टाइम ट्रैकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक शिवाशीष राय ने कहा कि ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के बाद भी बेहतर सेवा अनुभव देना कंपनी की प्राथमिकता है। क्यूडिजी के साथ यह साझेदारी बढ़ते ओन लेबल पोर्टफोलियो के लिए मजबूत सर्विस इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऑनसाइटगो के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल महिपाल ने कहा कि बेहतर आफ्टर-सेल्स सेवा ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। इस साझेदारी के माध्यम से तकनीक आधारित और ग्राहक-केंद्रित सर्विस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

3.10 लाख रुपए नकद, दो सिम कार्ड व एक मोबाइल फोन बरामद टेलीग्राफ टास्क और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 43.12 लाख की साइबर ठगी, महिला सहित 10 आरोपी पकड़ाए

हरिभूमि न्यूज़ ►► फरीदाबाद

घर बैठे पार्ट-टाइम नौकरी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 43.12 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने मामले में अब तक एक महिला सहित 10 आरोपियों को नोएडा दिल्ली गुरुग्राम व रोहतक से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस ने 3.10 लाख रुपए नकद, दो सिम कार्ड और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। सभी गिरफ्तार



आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया जबकि फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर-31

निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 15 मई 2026 को उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। इसके बाद टेलीग्राम के माध्यम से उसे घर बैठे पार्ट-टाइम नौकरी और ऑनलाइन टास्क पूरा कर अच्छी कमाई का लालच दिया गया। शुरुआत में उसे ई-कॉमर्स वेबसाइट के उत्पादों के लिंक पर क्लिक कर स्क्रीनशॉट भेजने जैसे आसान कार्य दिए गए और बदले में छोटी-छोटी रकम उसके खाते में भेजी गई। इससे पीड़ित का भरोसा जीतने के बाद उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

हरियाणा सरकार				निविदा सूचना	
क्र. सं. नाम	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि	राशि/ईएमडी (लाभ) ₹. में	विभाग की वेबसाइट
1	वन विभाग सिरसा	एनएचएआई स्कोम के तहत सिरसा डबवाली रैंज में नया पौधारोपण और कार्यों का रखरखाव।	14.07.2026 22.07.2026	99.71 लाख	https://etenders.hry.nic.in
2	बीपीएस राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत	मद अर्थात फॉल्स सीलिंग की अधिप्राप्ति + छह कार्यों के लिए निविदा हेतु विज्ञापन के प्रकाशन के सम्बन्ध में।	16.07.2026 23.07.2026	ईएमडी 70000	https://etenders.hry.nic.in
3	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 437 मर्चें तक मर्चें निहित सूची (437 मर्चों का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
4	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 01 मर्चें तक अर्थात स्पेक्ट्रोमीटर मर्चें निहित सूची (01 मर्च का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
5	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 34 मर्चें तक मर्चें निहित सूची (34 मर्चों का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
6	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 25 मर्चें तक मर्चें निहित सूची (25 मर्चों का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
7	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 22 मर्चें तक मर्चें निहित सूची (22 मर्चों का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
8	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 03 मर्चें तक मर्चें निहित सूची (03 मर्चों का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
9	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान पंचकुला, हरियाणा	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 01 से 13 मर्चें तक मर्चें निहित सूची (13 मर्चों का सिंगल लॉट) *	16.07.2026 19.08.2026		https://etenders.hry.nic.in
अधिक जानकारी हेतु कृपया पथारें: www.etenders.hry.nic.in			पीआरडीएच-11/2027/180/47210/I/88/7 दि. 15.07.26		

खबर संक्षेप

पुलिया से टकराई कार उड़े परखच्चे, 3 की मौत

लखनऊ। लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर बछरावां के खेरहनी गांव के पास सुबह बेकाबू कार पुलिया से जा टकराई। इससे कार सवार सिपाही, रिटायर दीवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार 100 किमी होने और चालक को झपकी आने के चलते हादसा हुआ।

बरेली में अब तक 58 शातिर गिरफ्तार

बरेली। डीजीपी के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत बरेली जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलवार को छठे दिन जिलेभर में 29 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 26.49 लाख रुपये, 69 मोबाइल फोन और 21 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। अब तक कुल 58 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का लेनदेन सामने आया है।

ब्राउन शुगर के दो तस्करों को रंगे हाथो दबोचा

रांची। लोहरदगा झारखंड के लोहरदगा जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ कुड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कुड़ थाना क्षेत्र के मानती पेट्रोल पंप के समीप वाहन जांच अभियान चलाकर 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में लोहरदगा जेल भेज दिया गया। कुड़ थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लोहरदगा एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा ने कार्रवाई का खुलासा किया। अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की 14 जुलाई की शाम करीब 5:00 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा-लोहरदगा मुख्य मार्ग से ब्राउन शुगर की एक बड़ी खेप बिक्री के लिए ले जाई जा रही है।

पेज एक का शेष

उनका जवाब था ...

परिश्रम करने के बावजूद मेरा टिकट नरोत्तम मिश्रा ने छीन लिया। 2014 में शिवराज जी ने आश्वासन दिया पूरा नहीं हुआ। भाग्य का खेल है, भाग्य जहां ले जाएगा, जाएंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। प्रश्न: किस बात से आपको ज्यादा हैरत है कि आप कांग्रेस से चुनाव प्रत्याशी नहीं हैं या भाजपा से नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी नहीं हैं ? उत्तर : मैं अकेला व्यक्ति हूं जो पिछले तीन महीने से यह कह रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को निराशा हाथ लगेगी। स्वयं को टिकट नहीं मिलने से हैरान हूं। लेकिन इससे ज्यादा हेरानी की बात है कि दत्तिया विधानसभा क्षेत्र में से तीन दलों में से जिनने सबसे अच्छी परिश्रम करके तैयारी की उनमें मैं, नरोत्तम मिश्रा जी और राजेंद्र भारती जी हम तीनों चुनावी परिदृश्य से बाहर हो गए और जो लोग दत्तिया में कहीं से भी सक्रिय नहीं थे ऐसे तीनों लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हैरत की बात यह है कि जिन्होंने पसीना बहाया वे बाहर हो गए हैं और जिन्होंने कभी परिश्रम नहीं किया, दत्तिया की जनता के लिए किसी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी वे खंब ठेकेकर चुनाव में खड़े हो गए हैं उनकी पाटियों ने उन पर भरोसा किया हम पर नहीं किया ज्यादा हैरत की बात तो यह है।

प्रश्न: आपको किस आधार पर ऐसी उम्मीद थी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा और आप इस बात का अफसोस नहीं है कि भाजपा में ही बने रहते तो आपको मौका मिल जाता ?

उत्तर: नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं होगा यह मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं लंबे समय से भाजपा में रहा हूं उसकी राजनीति समझता हूं जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा ने जातीय सम्मेलन अपने स्तर पर प्रारंभ किए, जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा के विभिन्न स्तर के बड़े नेताओं, मंत्रियों, निमित अध्यक्षों को दत्तिया में बुलाने का काम किया और वे आए भी, भाजपा में इसको अनुशासनहीनता माना जाता है और यह सब उनको माइनस मार्किंग हो रही थी यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। 2025 में शिवराज सिंह चौहान दत्तिया आए थे, नरोत्तम मिश्रा ने उनका बहिष्कार कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भांडेर और सेवढा में आए नरोत्तम मिश्रा उनसे मिलने नहीं गए। यहां एक हवाई अड्डे के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री और सांसद आए थे उस कार्यक्रम में उपज्व हुआ था और पुलिस के अधिकारियों के ट्रंफ़रकर हुए थे। सांसद तो लगातार इस बात से नाराज थीं कि उन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री का अपमान, सांसद की नाराजगी ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रही थीं। इसलिए, मुझे लग रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा।

प्रश्न: नरोत्तम को भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पूरा दत्तिया ठहर गया सड़कें जाम हो गईं, लोग भूखे-प्यासे सड़कों पर दिखने लगे। आपको कांग्रेस ने

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर जन भवन में मंथन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए अहम सुझाव

हरिभूमि न्यूज़ »» लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के साथ संवाद एवं रात्रिभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चुनाव सुधार, महिला आरक्षण, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, स्थानीय निकाय चुनाव, चुनावी व्यव और राजनीतिक संगठनों की भूमिका सहित कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

जन भवन में आयोजित संवाद के दौरान राज्यपाल ने समिति के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न रखा कि यदि किसी क्षेत्र में एक-दो वर्ष पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हों और नई व्यवस्था लागू होने के कारण दोबारा चुनाव कराने पड़ें, तो उम्मीदवारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार और चुनावी

राजनीतिक संगठनों की भूमिका सहित कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई



सीएम योगी ने कहा-पहले नौकरी निकलती नहीं थी और निकल गई तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल पड़ती थी

2017 से पहले तत्कालीन सरकार ही सबसे बड़ी अपशगुन थी: सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने बताया युवा शक्ति पर भरोसा, कहा- युवाओं के दम पर बनेगा वन ट्रिलियन डॉलर का उत्तर प्रदेश

टी एन मिश्र »» लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार था और न पारदर्शी भर्ती प्रणाली। सरकारी नौकरियों पर एक परिवार का अधिकार था और बिना पैसे कोई काम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकार की सोच व कार्यशैली बीमार थी। 2017 से पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन थी। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सवा तीन करोड़ से अधिक युवा व कारीगर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री बुधवार को विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रशिक्षित युवाओं से संवाद किया और उनके उत्पादों की सराहना की।

सीएम ने कहा कि इस वर्ष यूनेस्को ने विश्व युवा कौशल दिवस की थीम रसाइना भविष्य के लिए कौशल निर्धारित की है। अवसर तभी साकार होते हैं, जब दूरदृष्टि और सकारात्मक सोच वाली सरकार हो। दुनिया का सबसे अधिक युवा वर्ग उत्तर



प्रदेश में है और यह गवं का विषय है। यह हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम इस स्केल को स्किलिंग से जोड़कर युपी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा शक्ति किसी भी चुनौती का समाधान बन सकती है। युवाओं को सही दिशा, प्रशिक्षण व अवसर मिलें तो वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

पहले युपी के नाम से चिढ़ते थे बाहरी लोग

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने ऐसे हालात बना दिए कि बाहर के लोग युपी के नाम से चिढ़ते थे। कोई युवा डिप्लोमा या डिग्री लेकर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसे अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सरकारी नौकरियों पर एक खानदान का अधिकार था, पारदर्शिता का अभाव था। भर्ती प्रक्रियाओं में भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार हावी था। बिना पैसे कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि घनना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल दो ही खाता है। जिसके पास सीमित

आवश्यकता है, उसको नौद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वह ठीक से सो भी नहीं पाता। उसके लिए तो जीवन नर्क से बदतर है।

स्किल डेवलपमेंट को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश में कौशल विकास मंत्रालय का गठन कर स्किल डेवलपमेंट को नई पहचान और दिशा दी। इस युवाओं के रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। करीब 10 वर्ष पहले यहां मौजूद अधिसंख्य युवा छात्र थे और माता-पिता पर निर्भर थे। तब प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। स्कूल शिक्षा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी और युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। कानून-व्यवस्था की स्थिति भी कमजोर थी। न बेटियां सुरक्षित थीं।

योगी सरकार का बड़ा एक्शन, रिटायर्ड एआरटीओ के घर से 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना, नौ किलो चांदी और 1.62 करोड़ नकद और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद



हरिभूमि न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान यात्री विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त सहायक संग्रामीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। दो दिन तक चली इस कार्रवाई में विजिलेंस टीम ने 1 करोड़ 62 लाख रुपये नकद, करीब 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हॉरे एवं सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विजिलेंस के अनुसार ललित कुमार के

■ **डीजीपी राजीव कृष्णा ने की टीम को एक लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा**

व्यायालय से सर्व वारंट प्राप्त करने के बाद 7 और 8 जुलाई को अलीगंज स्थित आवास पर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी और राखरेली में मकान, फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज, दो लक्जरी कारें, एक रिवॉल्वर तथा बैंक खातों, ड्राफ्टर, क्यूबुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के रिकॉर्ड भी बरामद हुए हैं। विजिलेंस का कहना है कि सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस कार्रवाई के लिए लखनऊ सेक्टर की टीम को एक लाख रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है।

योगी सरकार का बड़ा एक्शन, रिटायर्ड एआरटीओ के घर से 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना, नौ किलो चांदी और 1.62 करोड़ नकद और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद



हरिभूमि न्यूज़ »» लखनऊ

लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया इलाके में पूर्वोत्तर रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुधवार को बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और इंजीनियरिंग विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। संयुक्त अभियान के तहत रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों, झोपड़पट्टियों और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया।

डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले कई बार नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के भीतर निर्माण नहीं हटाए गए। इसके बाद बुधवार को आरपीएफ, जीआरपी और इंजीनियरिंग विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू की।



यह अभियान मवैया तिवारी होटल से लेकर मछली मंडी तक रेलवे की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चलाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार राजनीतिक उपर्युद्ध का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा अगर मैंने समझौता किया होता, तो हमें इतनी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। जिन लोगों ने समझौता किया है, उनके पास अपने कई बैग और सामान हैं। यह बात उन्होंने उन नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कही जिन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है।

डा. अर्चना गुप्ता और राव इंद्रजीत के बीच मोदी और नाराय सरकार की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंचाने, संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के अनुभव का लाभ पार्टी और प्रदेश को निरंतर मिल रहा है। वहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा पार्टी की नीतियां और जनकल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगी। प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा का मजबूत संगठन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मोदी और नाराय सरकार विकास, सुरक्षासैन और जनकल्याण के संकरूप के साथ कार्य कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन और सरकार में सम्वत प्रयासों से हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

भारतीय रेलवे का नया ...
इतिहासिक क्षण से ठीक पहले, पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हस्तक्षेप आकाउंट पर इस आस्थाभूजिक ट्रेन की बेहद आकर्षक तस्वीरें साझा कीं और गर्व से लिखा कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा से चलने के लिए तैयार है। यह क्रांतिकारी कदम देश को कार्बन मुक्त और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन देने की दिशा में भारतीय रेलवे को सबसे बड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक सफलताओं में से एक है। देश की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर हरियाणा की धरती से शुरू होने जा रहा है। लगभग 90 किलोमीटर लंबे जॉइ-सोनीपत रेलखंड पर इस ट्रेन का तकनीकी परीक्षण पूरा हो चुका है। ट्रयाल के दौरान यह ट्रेन 75 किमी/घंटे की रफ्तार से बढ़ी। कंप्रेस्ड हाइड्रोजन लूप को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और ट्रेन में ईंधन भरने के लिए जॉइ में एक विशेष रिफिलिंग और स्टोरेज यूनिट का निर्माण किया गया है। रेलवे ने इस तकनीक को विशेष रूप से उन उन्नों के लिए तैयार किया है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बिजली के तार बिछाना बेहद मुश्किल और खर्चीला काम है। इस ट्रेन में 10 कोच होंगे, जो इन्हें बॉट गेज पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन बनाते हैं। ट्रेन को चलाने के लिए इसमें दो ड्राइविंग पावर कार लागाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1200 किलोवाट है। हाइड्रोजन गैस की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। ट्रेन को हाइड्रोजन लैंक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है, जो 24 घंटे सुरक्षा सिस्टम की निगरानी करेंगी।

रोहतक की गुनगुन ...

बीच आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी निधारित परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी।औरतकब है कि कंपनी सेक्टरी एजजीक्यूटिव एट्रेंस ट्रेस्ट कंपनी सेक्टरटी पाइथ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा है। इसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान संवर्धित करता है, जो कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है।

स्टीम से हाइड्रोजन तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चलेगी

भारतीय रेलवे का इतिहास केवल पटरियों के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि तकनीकी प्रगति व नवाचार की निरंतर यात्रा का दस्तावेज है। भाप से शुरू हुआ यह सफर डीजल और बिजली के पड़ावों से गुजरता हुआ अब हरित ऊर्जा के नए युग में प्रवेश कर रहा है। 17 जुलाई 2026 को हरियाणा का जींद इतिहास रचेगा, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद-सोनीपत रेलखंड से शुरू होने वाली यह सेवा तकनीकी नवाचार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ेगी। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा आज वैश्विक चुनौतियाँ हैं, जिनके चलते परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल बनाना अनिवार्य हो गया है। इस बदलाव की शुरुआत हरियाणा से होना विशेष महत्व रखता है। जींद-सोनीपत खंड का चुनाव राज्य के मजबूत बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता का परिचायक है। औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और नागरिक उड्डयन में हुए निवेश ने हरियाणा को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का स्वाभाविक केंद्र बना दिया है।

विकास के नए आयाम गढ़ता हरियाणा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से

हरियाणा में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री के कर-कमलों से 14700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा, जिनमें जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, भिवानी व नारनौल के चिकित्सा महाविद्यालय, दिल्ली-अम्बाला-कटरा हाईवे तथा अम्बाला-काला अम्ब और जींद-गोहाना नेशनल हाईवे शामिल हैं। साथ ही सिख संग्रहालय कुरुक्षेत्र और हांसी-बरवाला हाईवे का शिलान्यास भी प्रदेश के सांस्कृतिक और आधारभूत विकास को नई दिशा देगा। ये परियोजनाएं हरियाणा के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात, निवेश और रोजगार का सशक्त आधार बनेंगी और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करेंगी।

हाइड्रोजन ट्रेन-रेल तकनीक का भविष्य
हाइड्रोजन तकनीक फ्यूल सेल प्रणाली पर आधारित है, जिसमें संग्रहित हाइड्रोजन और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा बनती है और केवल पानी व ऊष्मा उपोत्पाद के रूप में निकलती है। कोई प्रदूषणकारी गैस नहीं। यह उन रेलमार्गों के लिए विशेष रूप से कारगर है जहां पूर्ण विद्युतीकरण व्यावहारिक नहीं है, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद



करती है। भारतीय रेलवे ने परिचालन, सुरक्षा और ऊर्जा प्रबंधन में भी व्यापक बदलाव किए हैं। तेज विद्युतीकरण, स्वदेशी सुरक्षा प्रणालियाँ और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने रेलवे को अधिक आधुनिक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाया है। हाइड्रोजन ट्रेन इसी दिशा की अगली कड़ी है, जो ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने में सहायक होगी। जर्मनी ने वाणिज्यिक हाइड्रोजन यात्री

ट्रेन सेवा शुरू करके इस तकनीक को वैश्विक मान्यता दिलाई व इसके बाद चीन सहित कई देशों ने भी इसके विकास व परीक्षण को गति दी है। भारत का यह कदम दर्शाता है कि देश केवल वैश्विक बदलावों का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की परिवहन प्रणालियों के विकास में सक्रिय भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जींद-सोनीपत सेवा भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनेगी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप रेल परिवहन में हाइड्रोजन तकनीक का समावेश ऊर्जा संक्रमण को तेज करेगा और भविष्य में उन रेल मार्गों के लिए भी नए विकल्प देगा जहां पारंपरिक विद्युतीकरण संभव नहीं है। हरियाणा का इस ऐतिहासिक पहल का पहला पड़ाव बनना राज्य के विकसित बुनियादी ढांचे और प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता का प्रमाण है। 17 जुलाई को जब यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर रवाना होगी, तो यह केवल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की उस नई सोच का प्रतीक होगी जिसमें तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय संवेदनशीलता साथ-साथ आगे

बढ़ते हैं। यह यात्रा आने वाले वर्षों में रेलवे के विकास को नई दिशा देगी और हरित, आधुनिक तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देने वाले एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच ने हरियाणा को देश की सबसे बड़ी हरित तकनीकी पहल का प्रथम साक्षी बनाया है, और यह मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैं मानता हूँ कि यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हरियाणा विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाएं यह सिद्ध करती हैं कि प्रधानमंत्री संदेव देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करने में विश्वास रखते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं हरियाणा की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करती रहेगी।

-नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा



कुछ मंत्रियों ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया, इसके बाद मामला कैबिनेट में डिफर हो गया

जहां डॉक्टर नहीं हैं, पहले वहां डॉक्टरों की भर्ती इसके बाद ही दूसरे अस्पतालों का उन्नयन होगा

हरिभूमि न्यूज़ ►► गोपाल

कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को अस्पतालों के उन्नयन, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम समेत तीन मुद्दों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंजूरी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल तो बन जाते हैं, पर डॉक्टरों की कमी की वजह से वह संचालित नहीं हो पाते। प्रदेश में ऐसे तमाम स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां एक भी डॉक्टर नहीं हैं। पहले उन अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती कराएं, इसके बाद ही उन्नयन के बारे में चर्चा करें। स्वास्थ्य विभाग में 73 उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन करने का मुद्दा मंजूरी के लिए रखा गया था।



कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से चर्चा करते सीएम डॉ. मोहन।

73 अस्पतालों के उन्नयन का रखा था प्रस्ताव

इसके बावजूद कैबिनेट में 73 अस्पतालों के उन्नयन का मुद्दा रखा गया। बताते हैं कि मंजूरी मिलने पर इन सभी अस्पतालों में उपकरणों के साथ ही टैक्निशियन से लेकर अन्य पदों पर भर्ती की जाती। इसके लिए 1600 डॉक्टरों की मांग रखी गई। इस पर कुछ मंत्रियों ने कहा कि डॉक्टरों की कमी प्रदेश भर में है। ऐसे में

अस्पतालों के उन्नयन से एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहले जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, वहां डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, इसके बाद ही उन्नयन हो। एक उदाहरण यह भी दिया गया कि राणगढ़ के खिकचौपुर के पास एक अस्पताल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है।

जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी

नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8 हजार 445 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में मूंग उपाजर्ज के लिए 1,587 करोड़ रुपए की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कुण्डलिया परियोजना को निरंतर रखने जैसे कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई है।

निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

रबी वर्ष 2023-24 विषण्ण वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। पंजाब नेशनल बैंक से ली गई साख सीमा में 19 जुलाई 2026 से 18 जनवरी 2027 तक 6 माह के लिए शेष राशि 396 करोड़ की निःशुल्क प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जाएगी।

एनसीएलटी के आदेश के बाद एंटरटेनमेंट सिटी के पुनर्विकास का मार्ग हुआ प्रशस्त

नई दिल्ली/नोएडा। हाल ही में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश के बाद भूटानी ग्रुप ने एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड से जुड़े मामले में आई कानूनी स्पष्टता का स्वागत किया है। ग्रुप ने कहा कि वह इस प्रतिष्ठित परियोजना के पुनर्विकास एवं पुनर्जीवन के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख स्थान पर स्थित एंटरटेनमेंट सिटी देश के सबसे बड़े मनोरंजन एवं लाइफस्टाइल परिसरों में से एक है। यहाँ द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, गार्डनस गैलरिया मॉल, वल्ड्स ऑफ़ वंडर थीम पार्क, वाओ वाटर पार्क, किडज़ानिया, होटल, रिटेल एवं अन्य प्रमुख मनोरंजन सुविधाएँ स्थित हैं। लगभग 147.4835 एकड़ में फैली यह परियोजना उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित मनोरंजन गंतव्यों में से एक रही है। भूटानी इफ्रा के सीईओ आशीष भूटानी ने कहा एनसीएलटी के हालिया आदेश से लंबे समय से चले आ रहे मामले में महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता आई है। हम इसे केवल एक कानूनी नियंत्रण नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और मूल्य सृजन के नए अवसर के रूप में देखते हैं।

भारत में लुलुलेमन का पहला स्टोर नई दिल्ली में खुलेगा

नई दिल्ली। लुलुलेमन ने भारत में अपने पहले स्टोर के पते की घोषणा आज की। यह नया स्टोर नई दिल्ली के डीएलएफ प्रोमेनेड में खुलेगा और टाटा क्लिक के साथ कंपनी के फ्रेंचाइजी समझौते के तहत इसी साल शरद ऋतु में बाद में शुरू होगा। इस स्टोर में मिलेंगे पुरुषों और महिलाओं के लिए हाई-परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, जो योग, पिलेट्स, रनिंग, ट्रेनिंग, टेनिस, गोल्फ और रोजमर्रा की गतिविधियों जैसी कई तरह की एक्टिविटीज में मददगार होंगे। यह स्टोर दिल्ली के फिटनेस लवर्स, एक्सपर्ट्स और ग्राहकों को एक साथ एक ही छत के नीचे लाने और उनके बीच दोस्ती व तालमेल बढ़ाने की बेहतरीन जगह बनेगा। स्टोर के शुरू होने के साथ-साथ टाटा क्लिक इस ब्रांड को अपने प्लेटफॉर्म टाटा क्लिक लग्जरी और टाटा क्लिक फैशन पर भी लाँच करेगा। लुलुलेमन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ईएमईए, सारा क्लार्क ने कहा भारत में लुलुलेमन को लाना हमारी टीमों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम दुनिया भर में अपने ब्रांड को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस ऑपनिंग की तैयारी के लिए हम नई दिल्ली के कम्युनिटी के साथ संबंध मजबूत करने के लिए टाटा क्लिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

डीएस ग्रुप ने पल्लू प्रोटेक्शन अभियान शुरू किया

नई दिल्ली। प्रमुख एफएमसीजी समूह और मल्टी-बिजनेस कॉर्पोरेशन, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप डीएस ग्रुप ने कृषि कार्य के दौरान कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के संपर्क से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से महिला किसानों की सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। कंपनी ने बागपत जिले के पाली, कथा, बांडपुर, सुनहरा, बसी, मावीकला और सांकरौध सहित सात गांवों में पल्लू प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य केवल महिला किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करना ही नहीं, बल्कि उन्हें उनकी जरूरतों और स्थानीय जीवनशैली के अनुरूप एक व्यावहारिक सुरक्षा समाधान भी उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत जागरूकता, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा उपायों को एक साथ जोड़ते हुए सुरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीएस ग्रुप ने इस अभियान के तहत पल्लू प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई - फिल्टर पेश किया है। डीएस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट मार्केटिंग राजीव जैन ने कहा महिला किसान भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन खेती के दौरान उन्हें जिन स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में जागरूकता अभी भी बहुत कम है।

ओडिशा के दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार तीन लग्जरी कारों से करोड़ों का गांजा जब्त

हरिभूमि न्यूज़ ►► जशपुरनगर

जशपुर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर एक ही दिन में तीन अलग-अलग कार्रवाई में 552 किलो गांजा जब्त किया है।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करों के दो तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ तीन लग्जरी कार जब्त किया है। एसएसपी लाल उमेश सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबियों से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से बड़ी मात्रा में तस्कर,छत्तीसगढ़ के जशपुर होते हुए दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मंगलवार की शाम को जिले के कुनकुरी, नारायणपुर, बगीचा और कांसाबेल



में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। नाकाबंदी के दौरान शाम लगभग साढ़े 6 बजे कुनकुरी के जय स्तंभ के पास पुलिस के जवानों ने तपकरा की ओर से आ रही एक

सफेद रंग की इनोवा कार को रूकने का संकेत किया। लेकिन पुलिस को देख कर कार चालक नाकाबंदी तोड़ कर भाग निकला। कुनकुरी पुलिस की टीम ने कार का पीछा किया।

ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और कुशवाह मतदाता बनेंगे जीत की कुंजी, उम्मीदवारों ने संभाला मैदान

समाजों के नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी

हरिभूमि न्यूज़ ►► गोपाल

दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़े इस चुनाव में विकास और संगठन के साथ-साथ जातीय समीकरण सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बनकर उभरा है। राजनीतिक दलों का पूरा फोकस उन समाजों पर है, जिनकी संख्या अधिक है और जो चुनावी नतीजे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें सबसे प्रमुख ब्राह्मण, अनुसूचित जाति (जाटव-अहिरवार) और काछी-कुशवाह समाज हैं।

दतिया विधानसभा क्षेत्र में अगले दो सप्ताह तक विभिन्न समाजों के प्रभावशाली नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बृथ स्तर तक पहुंचकर सामाजिक समीकरण साधने में जुटी हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है।

विस चुनाव का इतिहास भी दिलचस्प

दतिया विधानसभा में 1952 से अब तक 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस नौ बार जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं लगातार तीन बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम है। ऐसे में यह

उपचुनाव न केवल दोनों दलों की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने वाला चुनाव भी माना जा रहा है।

इन मतदाताओं पर सबकी नजर

दतिया विधानसभा में प्रमुख सामाजिक वर्गों के मतदाताओं का अनुमानित आंकड़ा इस प्रकार है

- अनुसूचित जाति (जाटव-अहिरवार): लगभग 60 हजार
- ब्राह्मण: लगभग 35 हजार
- काछी-कुशवाह: लगभग 27 हजार
- क्षत्रिय, पाल और बघेल : लगभग 25 हजार
- यादव : लगभग 18 हजार
- वैश्य : लगभग 15 हजार

सभी वर्गों के मतदाताओं को साधने के लिए दोनों प्रमुख दलों ने अलग-अलग समाजों के प्रभावशाली नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय किया है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 सीआरपीसी/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए
मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त **मोहम्मद इसलाम उर्फ सोनू**, पुत्र **मोहम्मद इफ्फान निवासी सी-22, गोकुलपुरी, दिल्ली-94** ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **98/2018**, धारा **33 दिल्ली एक्साइज एक्ट**, धाना **गोकुलपुरी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त **मोहम्मद इसलाम उर्फ सोनू** मिल नहीं रहा है और मुझे समामान्य रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **मोहम्मद इसलाम उर्फ सोनू** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **98/2018**, धारा **33 दिल्ली एक्साइज एक्ट**, धाना **गोकुलपुरी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **मोहम्मद इसलाम उर्फ सोनू** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक **24.09.2026** को या उससे पूर्व हाजिर हो।
आवेशानुसार सुश्री इसरा जैदी
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-04
कमरा नं. 64, चौथा तल, उत्तर पूर्व जिला कड़कड़डुगा कोर्ट्स, दिल्ली
DP/9662/NE/2026

चिंतन

ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बीच यूके से एफटीए

वैश्विक व्यापार इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर आर्थिक दबाव की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होना आर्थिक सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि आज दुनिया में व्यापार केवल वस्तुओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कूटनीति, रणनीति और राष्ट्रीय हितों का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। अमेरिका की प्रस्तावित टैरिफ नीति का निशाना रूस की ऊर्जा आय को कम करना है, लेकिन इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। भारत आज रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। सस्ते रूसी तेल ने भारत को महंगाई नियंत्रित रखने, ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद की है। ऐसे में यदि रूस से तेल खरीदने के आधार पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की कोशिश होती है, तो यह केवल व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति होगी। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। इसी बीच भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते का लागू होना भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। यह समझौता केवल टैरिफ घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में लगभग शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने से वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर भारतीय उपभोक्ताओं को ब्रिटेन से आने वाली कारों, स्कॉच विस्की, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल उपकरण और कई प्रीमियम उत्पाद अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। हालांकि, एफटीए का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब भारतीय उद्योग गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादकता के स्तर पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। केवल आयात सस्ता होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्यात बढ़ाना और घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुक्त व्यापार का लाभ किसानों, एमएसएमई और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ समृद्धि के पक्षे खोलते हैं। भारत के लिए सही रास्ता यही है कि वह दबाव की राजनीति से अप्रभावित रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और एफटीए जैसे समझौतों के जरिए वैश्विक बाजार में अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत बनाए। यही संतुलित नीति भारत को बदलती विश्व व्यवस्था में एक भरोसेमंद और प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

रक्षा प्रणाली
प्रमोद भार्गव



लंबी जंग की तैयारी के लिए सक्षम होता भारत

ऑपरेशन सिंदूर की छोटी लड़ाई के बाद भारत रक्षा-रणनीति में बदलाव के ऐसे संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान या अन्य किसी देश से लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़े तो उसकी युद्ध क्षे्र में सक्षमता बनी रहे। नतीजतन पिछले सवा साल में भारत ने हथियार व अन्य उपकरणों की बड़ी खरीद की है अथवा उसकी तैयारी चल रही है। अतएव स्पष्ट संकेत है कि तीनों सेनाओं को अब सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि लंबी और बहुस्तरीय लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। रक्षा क्रियान्वयन सलाहकार परिषद ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए संघर्ष के बाद 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल कीमत 9.80 लाख करोड़ रुपये हैं। यह राशि कई वर्षों में धीरे-धीरे खरीद सौदों, निर्माण कार्यों और योजनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होगी। हाल ही में भारतीय निजी उद्योगपतियों को भी बड़ी रक्षा सामग्री के निर्माण की अनुमति दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर तीन नौसैनिक जहाजों आइएनएस दुनागिरी, आइएनएस संशोधक और आइएनएस अग्रय को नौसेना के बेड़े को सुपुर्द करते हुए कहा है कि ‘कोई भी राष्ट्र समुद्र में अपनी क्षमता बढ़ाए बिना बड़ी शक्ति नहीं बन सकता है। ये संकेत स्पष्ट करते हैं कि ये तैयारियां भारत को सामरिक दृष्टि से वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण बना रही हैं। इन खरीदों में टैंक, तोप, ड्रोन, एयरडिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए एआई नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता को विकसित करने के बड़े संकेत हैं। दरअसल रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास और अमेरिका-ईरान तथा पश्चिम एशिया के देशों में चल रहे युद्ध को देखते हुए भारत की सैन्य सोच बदली है। हालांकि पनडुब्बियों और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की भी बड़ी संख्या में जरूरत है। भारत ने मार्च 2025 में 54 हजार करोड़, जुलाई में 1.05 लाख करोड़, अगस्त में 67 हजार करोड़, अक्टूबर में 79 हजार करोड़ की रक्षा सामग्री खरीद के प्रस्ताव अलग-अलग करों को दिए हैं। फरवरी 2026 में 3.6 लाख करोड़ की रक्षा सामग्री खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ 114 नए सफल विमान भी खरीदे जा रहे हैं। इसी माह जुलाई में 52 हजार करोड़ की सामग्री सैन्य-बलों की जंगी क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। साफ है, भविष्य में भारत का किसी देश से युद्ध होता है तो वह लंबी लड़ाई की सामर्थ्य दिखाने में अग्रणी रहेगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो तीन युद्धपोत सेना में शामिल किए गए हैं, उनसे वाकई भारत की समुद्र में ताकत बढ़ी है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी में ही निर्मित युद्धपोत और पनडुब्बियां समुद्र में तैनात कर दिए हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाले ये जहाज और पनडुब्बियां भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ देश की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में इनके निर्यात के द्वार भी खुल जाएंगे। अतएव पश्चिम बंगाल की ब्लू इकोनोमी का बड़ा केंद्र बन जाएगा। भारत में नौसैनिकों की सुविधाओं के लिए 45 बड़े प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जा रहे हैं। आइएनएस दुनागिरी अत्याधुनिक हथियारों और संवेदनशील प्रणालियों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल से संपन्न है।

ब्रह्मोस सतह से सतह और सतह से आकाश तक शत्रु पर सटीक हमला करने में युद्धपोत पर लगे नवीनतम उपकरण एवं स्टेलथ तकनीक के कारण यह मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती है। इसकी इस विश्वश्लाघा के चलते ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। आइएनएस संशोधक देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इसे नटीय क्षेत्रों व गहरे समुद्री इलाकों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने तथा रक्षा एवं नगरिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। आइएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों और अन्य खतरों का मुकाबला करने में इसे अत्यंत प्रभावी माना जा रहा है। यह टारपीडो, स्वदेशी रॉकेट लांचर और उथले जल के लिए विकसित सोनार प्रणाली से लैस है। इसके चलते समुद्र के भीतर गुप्त खतरे का इसे पता चल जाता है। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की इस क्षमता ने भारत को पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बना दिया है। इस उपलब्धि से समुद्र में भारतीय हितों की रक्षा का अभियान और प्रभावी ढंग से चलाया जा सकेगा। इसके पहले भारत स्वदेशी तकनीक से परमाणु पनडुब्बी आईएनएस ‘अरिहंत’ का निर्माण 2009 में शुरू करने के 2013 में इसे समुद्र में जलावाहन भी कर चुका है। इस स्वदेशी परमाणु चालित पनडुब्बी अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू होना हमारी स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम था।

(लेखक स्वतंत्र संस्मकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विश्व में उस परिवर्तनकारी सोच का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें सहकारिता को केवल डेयरी, चीनी या बैंकिंग तक सीमित नहीं किया जाएगा अपितु सहकारिता का विस्तार जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स, हरित ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को समेकित करते किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक दृष्टि पर बहसें होंगी। देश के उत्थान पॉलिसीज पर कार्य करने वाले चेंजमेकर यह मान रहे हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक दृष्टि पर बहसें होंगी। देश के उत्थान पॉलिसीज पर कार्य करने वाले चेंज मेकर यह मान रहे हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय संभावनाओं का संस्थागत स्वरूप है।

आत्मसंयमी होना श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम लक्षण

आत्मसंयम मनुष्य की ऐसी आंतरिक क्षमता है, जिसके आधार पर मनुष्य अपना समग्र विकास करने में सक्षम होता है। बुरी आदतों पर नियंत्रण आत्मसंयम की शक्ति से ही संभव है। असल में यही खराब आदतें हमारी प्रगति की राह में अवरोध बनती हैं। यदि दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मसंयम में सही ताल मिल जाए तो असंभव से लक्ष्य को भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। संयम एक ऐसा बीज भंज्र या आवरण है, जो हर स्थिति में कारगर होता है। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन यही संदेश देता है कि उनके उत्कर्ष में आत्मसंयम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आत्मसंयमी होना श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम लक्षण है। जिन लोगों में आत्मसंयम होता है उनका स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति और करियर अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। ऐसे लोग जीवन से अधिक संतुष्ट रहते हैं। उन्हें जीवन अधिक सार्थक लगता है। आत्मसंयम का जीवन रचनात्मकता से ओतप्रोत होता है। यह सद्गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय को दूर करने के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई एवं गंभीरता प्रदान कर उसके जीवन को सुखप्रद बनाता है। आत्मसंयम का महामंत्र आत्मसात कर हम असीमित इच्छाओं के अश्व की लगाम अपने हाथ में रख सकते हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो संयमी की यात्र करने से शंकर बनने की है। हमें अपने जीवन में आत्मसंयम की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है, ताकि हम पथ से भटकें बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकें।



करंट अफेयर

ग्रेट बैरियर रीफ के लिए खतरा बना है जल प्रदूषण

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लैचिंग) को आमतौर पर ग्रेट बैरियर रीफ के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन दुनिया की इस सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली के सामने खराब जल गुणवत्ता भी एक गंभीर चुनौती है। खेती, शहरों और वन क्षेत्रों से बहकर नदियों में पहुंचने वाली मिट्टी (तलछट) समुद्र में दूर तक पहुंच जाती है। इसकी अधिक मात्रा प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास (सीग्रस) के मैदानों को ढक सकती है, जबकि उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष स्थिति को और खराब कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, लेकिन जल गुणवत्ता ऐसा मुद्दा है जिस पर ऑस्ट्रेलिया सीधे कार्रवाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ने हाल के वर्षों में बार-बार इस पर चिंता जताई है। वर्ष 2023 के बाद जारी चौथे मसौदा निर्णय में भी जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ खराब जल गुणवत्ता को प्रमुख खतरा बताया गया है। मसौदे में 2024-25 में प्रवाल विरंजन, खराब जल गुणवत्ता, मछली पकड़ने के ऐसे गैर टिकाऊ तरीके और तटीय भूमि के अनुचित उपयोग से हुए नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।



से हालांकि पता चला है कि जो लोग बगीचों और आवंटीत जमीनों में फसल और सब्जियां स्वयं उगाते हैं, वे औसतन केवल 3.4 किलोग्राम फल और सब्जियां बर्बाद करते हैं - जो ब्रिटेन के औसत से 95 प्रतिशत कम है। इन परिवारों ने भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए विभिन्न प्रथाओं को अपनाया, जिसमें अपनी अतिरिक्त उपज को संरक्षित करना या किसी अन्य को दे देना भी शामिल है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन और अन्य जगहों पर बगीचों, सामुदायिक उद्यानों और आवंटीत भूमि पर ताजा फसल एवं सब्जियां उगाने में दिलचस्पी फिर से बढ़ी है।

कर रहे हैं। वास्तव में वास्तविक विश्वविद्यालय वही है जो वास्तविक जीवन मूल्य परिवर्तन का माध्यम बने। नए जीवन की शुरुआत प्रथम दीक्षांत समारोह से जो शुरू करने जा रहे हैं वे रिश्क में नहीं हैं, अपितु वे सन्देश दे रहे हैं कि जीवन मूल्य भी अब सहकारिता से सुरक्षित होंगे। यह सहकारिता में नए आकाश में नई उड़ान है, चाहे कोई माने या न माने। यह उड़ान निःसंदेह सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के संकल्पों से संभव हो पा रही है, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात न होगी। हम सभी आज यह महसूस करने लगे हैं कि भारत की सहकारी व्यवस्था आज विश्व की सबसे बड़ी जन



आधारित आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी संस्थाओं से जुड़े हैं। किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, कारीगरों और ग्रामीण युवाओं के लिए सहकारिता केवल संस्था नहीं, बल्कि अवसर का द्वार है। लाभ और लोकहित के बीच संतुलन स्थापित कर नवाचार हेतु विकास का माध्यम सहकारिता बनने जा रही है। सहकारिता का प्राण उसके नैतिक मूल्यों में निहित है। विश्वास, पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक निर्णय, ये वे आधार हैं जिन पर सहकारिता का विशाल भवन खड़ा हुआ है। यदि इन मूल्यों के साथ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय दायित्वबोध लेकर ऐसे चरित्रवान नेतृत्व का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

विशेष विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि यह विश्वविद्यालय सहकारिता के नए पक्षियों के कलव से लोकमंगल का माध्यम बनने वाला है। जो 302 विद्यार्थी एवं 2 स्कॉलर को स्नातक एवं पीएचडी की उपाधि मिली है, यह तो एक शुरुआत है। केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर ने गुजरात के आणंद में ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालय के प्रथम



संकलित
प्रेरणा

आज की पाती 

होर्मुज संकट : विश्व आर्थिकी के लिए बढ़ता खतरा

अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। यदि यह समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार व्यवस्था प्रभावित होगी। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय संघर्ष अब वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। प्रतिदिन दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। जहाजों की आवाजाही अगर बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आना स्वाभाविक है। - *सुभाष यादव, बलौदाबाजार*

ऑफ बीट

जीवन यापन के बढ़ते खर्च से लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले (जिनका आहार अबसर समुचित नहीं होता है), के लिए स्वस्थ आहार का खर्च उठा पाना कठिन होता जा रहा है। इसके बावजूद, ब्रिटेन में घरों में हर साल आश्चर्यजनक मात्रा में भोजन बर्बाद होता है। इसमें लगभग

68 किलोग्राम फल और सब्जियां भी शामिल है। खाने की बर्बादी न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। वैश्विक स्तर पर, हर साल 1.3 अरब टन भोजन बर्बाद हो जाता है, जिससे दुनिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग आठ प्रतिशत उत्पन्न होता है। ये उत्सर्जन खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में अप्रयुक्त भोजन से उत्पन्न होता है। हमारे हालिया अध्ययन

से हालांकि पता चला है कि जो लोग बगीचों और आवंटीत जमीनों में फसल और सब्जियां स्वयं उगाते हैं, वे औसतन केवल 3.4 किलोग्राम फल और सब्जियां बर्बाद करते हैं - जो ब्रिटेन के औसत से 95 प्रतिशत कम है। इन परिवारों ने भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए विभिन्न प्रथाओं को अपनाया, जिसमें अपनी अतिरिक्त उपज को संरक्षित करना या किसी अन्य को दे देना भी शामिल है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन और अन्य जगहों पर बगीचों, सामुदायिक उद्यानों और आवंटीत भूमि पर ताजा फसल एवं सब्जियां उगाने में दिलचस्पी फिर से बढ़ी है।

विचार हरिभूमि 8

सहकारिता के नए आकाश में नई उड़ान

दीक्षांत समारोह में कहा भी कि नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” के संकल्प तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थापित ‘त्रिभुवन’ सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र के लिए एक मील का पथर है। यह यूनिवर्सिटी भविष्य के सहकारी नेतृत्वकर्ताओं, शोधकर्ताओं और पेशेवर प्रबंधकों को तैयार कर भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा और नई गति प्रदान करेगी। यह बात शत-प्रतिशत सही भी है और उनके प्रयासों का एक तरह से अभिनंदन भी है। सहकारिता को नया बौद्धिक आधार ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना से जो मिलने लगा है, जिसने ज्ञान, शोध, नवाचार और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है तो ऐसे ऐतिहासिक पहल को स्वर्णाक्षरों में अंकित भी किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की जानी चाहिए। दरअसल, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय उस विश्वास का प्रतीक अब बनने जा रहा है, जो संगठित समाज की शक्ति व किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पहल है। भारत इससे विश्व की सहकारिता को टक्कर देगा और देश को सशक्त बनाएगा, इसे नहीं भूलना चाहिए। महिला डिग्रीधारिकों की एक नई भूलावा चाहिए। प्रयोगशाला होगी। महिलाएं सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेंगी, यह विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में शामिल होने जा रहा है।

हम खुद विश्व जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से सशक्त बनकर और भारतीय जनमानस को सशक्त बनाकर सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ विकास का नया मार्ग तैयार करेंगे। सहकारिता विश्वविद्यालय के संबंध में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में इसके उद्देश्यों को विस्तार से रखा तो इसके बारे में जो भी कल्पनाएं लोग किए हों, लेकिन अब तो इस विश्वविद्यालय से सैकड़ों छात्र व शोधार्थी उपाधि प्राप्त करके भारत देश की सेवा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब जो अनमने ढंग से इस पहल की आलोचना करते रहे होंगे उनके लिए भी एक सीख है कि देश के लिए पहले अपने मन में इच्छा पैदा करो, उसे संजोकर उसकी संकल्पना को स्वरूप दो और फिर उसे स्थापित करके मिसाल के रूप में पेश करो। अमित शाह की प्रसन्नता की अनुभूति निःसंदेह असीमित होगी क्योंकि सहकारिता के नए आकाश में नई उड़ान की यह देशव्यापी हर्ष व उल्लास की बेला है।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में डेयर प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपने प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।



ट्रेड एग्रीमेंट

आज से भारत-यूक्रे कोईप्रदैन्याव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। उम्मीद है कि यह अहम समझौता 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को \$100 बिलियन तक पहुंचाएगा। -**अन्वपूर्णा देवी**, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

अंतरिक्ष उड़ान

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा है। यह मिशन नई हिस्रॉट, टेक्नोलॉजी में इन्वोल्वेशन और अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगा। - **समाट चौधरी**, सीएन, बिहार

पारदर्शी परीक्षा प्रणाली

पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हर छात्र का अधिकार है। कग्रेस पार्टी देश भर में छात्रों के इस अधिकार के लिए लड़ रही है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या और भी गंभीर है, जहां व्यापम, पटवारी भर्ती, कॉन्स्टेबल भर्ती और नर्सिंग कॉलेज जैसे चोटाले हुए हैं। - **कमलनाथ**, पूर्व सीएन, मध्यप्रदेश

दर्शकों का अपमान

फिल्मों पर सेंसरशिप असल में दर्शकों का अपमान है। स्मार्टफोन और बेहिसाब जानकारी तक पहुंच के इस दौर में, यह सोचना कि सरकार की बनाई कंसेट किसी सच्चाई के बारे में फिल्ममेकर के नजरिए से बालिदा लोगों को बचा सकती है, ये सिर्फि पुरानी सोच है, बल्कि बेकूफी भी है। - **रामगोपाल वर्मा**, फ़िल्मकार

अपने विचार हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फ़ैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

राजस्थान विधान सभा के स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विधान गौरव यात्रा’ में बोले लोकतंत्र केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, जनविश्वास और सेवा-भावना से सशक्त होता है : बिरला

▶▶ भूतपूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन’ में लोक सभा अध्यक्ष ने संबोधन दिया

▶▶ सशक्त और सार्थक बहस लोकतंत्र की पहचान है; सदन की गरिमा और मर्यादा हर परिस्थिति में बनाए रखना आवश्यक है

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि विधानमंडल केवल कानून बनाने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि वे लोकतंत्र की ऐसी ‘पाठशालाएं’ हैं जहां जनप्रतिनिधि संवाद, अनुशासन, सहमति और सेवा के मूल्यों का संस्कार प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि

जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपने दायित्वों का पूर्णतः बोध होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि जनविश्वास, संवाद, गरिमा और सेवा-भावना से सुदृढ़ होता है। बिरला राजस्थान विधान सभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत ‘विधान गौरव यात्रा : भूतपूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान विधान सभा को अपने सार्वजनिक जीवन की ‘प्रथम पाठशाला’ बताते हुए बिरला ने कहा कि इसी सदन में अर्जित लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय परंपराएं और विधायी आचरण ने उन्हें छात्र नेता से विधायक, सांसद और अंततः लोक सभा अध्यक्ष बनने की यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि विधान सभा में उन्होंने संसदीय लोकतंत्र का वास्तविक



स्वरूप समझा कि सुनने की संस्कृति और स्वस्थ बहस लोकतंत्र को समृद्ध बनाती है तथा इतिहास का निर्माण करती है, जबकि व्यक्तिगत मतभेद लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली प्रत्येक बहस और प्रत्येक शब्द लोकतांत्रिक इतिहास का स्थायी हिस्सा बन जाता है। युवा जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देते हुए बिरला ने उन्हें निरंतर अध्ययन, ध्यानपूर्वक सुनने तथा

सदन की कार्यवाही में सार्थक सहभागिता की आदत विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता पद नहीं, बल्कि आचरण को याद रखती है तथा अध्ययनशील और विषय का गहन ज्ञान रखने वाला जनप्रतिनिधि ही जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकता है। उन्होंने सदस्यों को सलाह दी कि वे भाषणबाजी के स्थान पर तथ्य, तर्क और रचनात्मक बहस को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता, ईमानदारी और समाज के साथ सतत संवाद अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति का अंतिम उद्देश्य जनसेवा और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। राजस्थान विधान सभा की लोकतांत्रिक यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देते हुए बिरला ने कहा कि राज्य की

लोकतांत्रिक चेतना केवल विधान सभा के इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन संवाद, विचार-विमर्श और सहभागी शासन व्यवस्था की परंपराओं में गहराई से निहित है। उन्होंने कहा कि सभा और समिति की परंपरा, स्थानीय स्वशासन तथा जनभागीदारी राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रही है, जिसे पंचायतों और प्रतिनिधिक संस्थाओं ने निरंतर सशक्त बनाया है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष वासुदेव देवानी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उपस्थित थे। कार्यक्रम में अनेक सांसद, पूर्व सांसद, राजस्थान सरकार के मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व विधायक तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्वलेव में सहभागिता शिवराज ने कृषि क्षेत्र को स्टार्टअप, स्किलिंग और एग्रीटेक से ताकत देने की अपील की

महिला किसान, स्वयं सहायता समूह और गावगीण उद्यमिता पर चौहान का खास जोर

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्वलेव 2026’ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएसआर को भारतीय परंपरा की ट्रस्टीशिप भावना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश हमें सब कुछ देता है, इसलिए कॉर्पोरेट जगत अपनी कमाई का हिस्सा किसानों, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण समाज के हित में समर्पित कर देश के विकास में साझेदार बने। चौहान ने जोर देकर कहा कि रिसर्च लैब में कैद न रहे, बल्कि ‘विज्ञान से किसान तक’ का पुल बने, ताकि जलवायु अनुकूल खेती, मृदा स्वास्थ्य, पोषण-सुरक्षित भोजन, कृषि कौशल विकास और महिला किसानों की उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सीएसआर निवेश से वास्तविक जमीन स्तर पर बदलाव दिखे। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कॉन्वलेव के दौरान रखे गए पांच थीम्स की चर्चा करते हुए कहा कि

कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना, मृदा स्वास्थ्य बचाना, किसानों की आय और स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षित करना और पोषण-समृद्ध, ऋतु-अनुकूल भोजन की संस्कृति को बढ़ाना, आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन घटने, बिना परीक्षण के उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से हो रही क्षति पर चिंता जताई और कहा कि मिट्टी बचेगी तो भूस भी बचेगा, इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे प्रयासों को सीएसआर के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है। चौहान ने कहा कि यह कॉन्वलेव एक ऐसा समागम है जिसमें कॉर्पोरेट जगत, मंत्री, वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान सभी एक ही मंच पर जुड़े हैं, जैसे कृषि के लिए एक कम्पलीट वैल्यू चेन बन गई हो। उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जिनके पास अधिक धन है, वे उसके मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी हैं और वह धन मूलतः समाज का धन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए-नए रिसर्च लैब में ही न रह जाएं, बल्कि सीधे किसान के खेत तक पहुंचें। उन्होंने ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों को किसान के बीच जाकर नई कृषि पद्धतियों, नई किस्मों और अनुसंधान की जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया। उनका स्पष्ट कहना रहा कि ‘विज्ञान से किसान तक’ की यात्रा तेज करनी होगी और इसमें कॉर्पोरेट जगत का सहयोग निर्णायक हो सकता है। जूट क्षेत्र के उदाहरण देते हुए चौहान ने बताया कि पहले रेशा निकालने के लिए 25 दिन तक पानी में भिगोकर रखना पड़ता था, जिससे पानी की कमी और खराब क्वालिटी की समस्या आती है, जबकि टेक्नोलॉजी के उपयोग से अब ऐसी मशीनें विकसित हुई हैं जो कम समय में बेहतर रेशा निकालने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मशीनों का जल्दी से जल्दी कमर्शियलाइजेशन हो, ताकि किसान तक यह तकनीक पहुंचे, यह काम अकेला सरकारी सेक्टर नहीं कर सकता, इसमें प्राइवेट सेक्टर की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

पीएसी बैठक में बोले वेणुगोपाल सड़क सुरक्षा, टोल निर्माण गुणवत्ता पर मंथन, कमियों को दूर करने का भरोसा

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक में बुधवार को देश में सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क, विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज), लेवी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ हुई बैठक सकारात्मक और सार्थक रही।

वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने पहले संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी कई कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। उन्होंने कहा कि समिति ने सड़क सुरक्षा के साथ-साथ टोल व्यवस्था और उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया था। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उनके अनुसार, एनएचएआई ने समिति द्वारा उठाई गई कई प्रमुख चिंताओं पर कार्रवाई की है और अनेक महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि संसद की लोक लेखा समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लिया गया और राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर सुधार की दिशा में ठोस पहल की गई है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय संसद की समिति के सुझावों को लागू करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता, सुरक्षा और पारदर्शिता को और बेहतर बनाएंगे। साथ ही टोल और अन्य यूजर चार्ज से जुड़े मामलों में भी आम लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक लेखा समिति समय-समय पर विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक परियोजनाओं की वित्तीय जवाबदेही, कार्यप्रणाली और प्रदर्शन की समीक्षा करती है तथा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सुधारात्मक सुझाव देती है। इस बैठक में सार्वजनिक अवसरचना पर लगाए जाने वाले शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।

सुप्रिया सुले ने कहा ‘परिसीमन बिल’ पर पवार गुट केंद्र सरकार के साथ

एजेंसी ▶▶ मुंबई

महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आइ हैं कि



शरद पवार की पार्टी (राकंपा) के कई विधायक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। इन सब अटकलों के बीच बुधवार को एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बुधवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का समर्थन करेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह शर्त रखी कि केंद्र सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान करे। सुले का यह ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि एसपी ने बजट सत्र में परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े केंद्र के संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया था। अब पवार की पार्टी के अंदर दल की राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चा है। कुछ दिनों में एसपी के नेताओं की भाजपा के सीनियर नेताओं संग कई बैठकें भी हो चुकी हैं



Narendra Modi
Prime Minister



MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LTD.



Dr. Mohan Yadav
Chief Minister



INFINITE POSSIBILITIES
INVEST
MADHYA PRADESH
GLOBAL INVESTORS SUMMIT
JANUARY 2027 | BHOPAL

Madhya Pradesh

Building Momentum Towards

Global Investors Summit 2027

Interactive Session
with
Dr. Mohan Yadav
Chief Minister



ON INVESTMENT OPPORTUNITIES IN MADHYA PRADESH
The Leela Palace



ROUND TABLE MEETING ON OPPORTUNITIES IN THE TEXTILE SECTOR
Bharat Mandapam

16 July, 2026 | New Delhi

LIVE STREAMING

 @Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh

 @Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP

 **jansamparkMP**

sws.Invest.mp.gov.in

Released by the Department of Public Relations, MP

D-11062/26
Designed by MP, Madhyam/2026

	धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। कारोबार का विस्तार हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।
कन्या	
	वर्धन के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। धन की स्थिति सन्तोषजनक रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
तुला	
	क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। आत्मविश्वास से लंबेज रहेगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है।
वृश्चिक	
	पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के योग्य बन रहे हैं। भाग-दौड़ अधिक रहेगी। खर्च अधिक रहेगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
धनु	
	आलस्य की अधिकता रहेगी। कारोबार का विस्तार होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। बहन-भाइयों का सहयोग मिलेगा।
मकर	
	कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। कुटुम्ब के किसी पुत्रुग में धन की प्राप्ति हो सकती है। आय में वृद्धि होगी। बातचीत में संयत रहें।
कुम्भ	
	शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा, परन्तु शैक्षिक कार्यों में कठिनाई भी आ सकती है। जीवनसाथी से मतभेद बढ़ सकता है। सुखद समाचार मिलेगा।

